IASbaba's Daily Prelims Test [Day 38]

Polity - Emergency Provisions & Judiciary and Economic Survey

1. भारत के संविधान ने अचानक उत्पन्न होने वाली कठिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भी युद्ध की वास्तविक घटना से पहले घोषित किया जा सकता है
2. यह राज्य के एक विशेष जिले पर घोषित किया जा सकता है
3. यह हर छह महीने में तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक समय-समय पर मंजूरी से जारी किया जा सकता हैं

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. केवल 2 और 3
2. केवल 1 और 3
3. केवल 1 और 2
4. 1, 2 और 3

Solution (3)

अनुच्छेद 352 के तहत, भारत की सुरक्षा या इसका कोई हिस्सा युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की धमकी से ग्रस्त हो तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते है , अगर वह संतुष्ट हो जाते है की वह एक आसन्न खतरा है।

इसके संचालन के लिए निर्धारित कोई अधिकतम अवधि नहीं है। यह हर छह महीने के संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है।

2. भारत में न्यायपालिका के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. न्यायपालिका राज्य का हिस्सा नहीं है
2. मुंसिफ की अदालत में दोनों सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार है
3. जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां दोनों का प्रयोग करते है।
4. राज्यों में पैटर्न और अधीनस्थ अदालतों के पद पर नियुक्ति एक समान नहीं हैं

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 3 और 4
2. 1 और 3
3. 2 और 3
4. 2, 3 और 4

Solution (1)

अपने सभी एजेंसियों को शामिल करने के लिए राज्य को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, यहां तक कि एक निजी निकाय या राज्य का एक साधन के रूप में काम कर रहे एक एजेंसी के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ के भीतर गिर जाता है। इसलिए, न्यायपालिका राज्य का एक हिस्सा है।

जिला मुंसिफ न्यायालय (वैकल्पिक वर्तनी जिला मुंसिफ कोर्ट) भारत में नागरिक मामलों से संबंधित सबसे कम आदेश से निपटने के मामलों की अदालत है।

अधिकार क्षेत्र और अधीनस्थ न्यायपालिका के संगठनात्मक ढांचे, का नामकरण राज्यों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए, वे राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ा भिन्न होते हैं.

जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। उनके पास मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ दोनों सिविल और आपराधिक मामले होते हैं। दूसरे शब्दों में, जिला न्यायाधीश भी सत्र न्यायाधीश है। जब वह नागरिक मामलों में सौदा करते है, वह जिला न्यायाधीश के रूप में जाने जाते है और जब वह आपराधिक मामलों को सुनता है, तब वह सत्र न्यायाधीश के रूप में जाने जाते है। जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां दोनों का प्रयोग करते है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति मांग का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है
2. अनुच्छेद 356 कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है
3. एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति मांग का प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. केवल 2 और 3
2. केवल 1 और 3
3. केवल 1 और 2
4. 1, 2 और 3

Solution (2)

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही घोषित किया जा सकता है न की अनुछेद 356 या राष्ट्रपति शासन पर।

राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति के एक संकल्प के निम्नलिखित दो मामलों में एक घोषणा की निरंतरता का अनुमोदन करने वाला संकल्प अलग है:

1. पहला केवल लोक सभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है जबकि दूसरा एक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने की जरूरत है।

2. पहला केवल एक साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जा सकता है जबकि दूसरा एक विशेष बहुमत द्वारा अपनाई जाने की जरूरत है।

4. सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।
2. सलाहकार क्षेत्राधिकार पूर्व संवैधानिक संधियों पर बना संदर्भों के बाहर उत्पन्न होने वाले विवादों में प्रयोग किया जा सकता है।
3. जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय चाहते हैं, तो वह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है।
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार लोक महत्व के किसी भी कानून में प्रयोग किया जा सकता है

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 1, 3 और 4
2. 1 और 2
3. 2 और 4
4. 1, 2 और 3

Solution (3)

संविधान (अनुच्छेद 143) दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करता है:

1) कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी सवाल पर उत्पन्न हुई या जिसके पैदा होने की संभावना है |

2) किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौते, वाचा, सनद या अन्य उपकरणों से उत्पन्न किसी भी विवाद पर। न तो अनुसूचित जाति सलाह देने के लिए बाध्य है ना ही सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

5. राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की साथ

1. राज्य विधायिका या तो निलंबित की जाती है या भंग हो जाती है
2. अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया हैं
3. संसद राज्य बजट पारित करता है
4. राष्ट्रपति राज्य शासन के प्रशासन के लिए अध्यादेश एलान कर सकते है

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. केवल 1 और 2
2. केवल 1 और 3
3. 1, 3 और 4
4. 1, 2 और 3

Solution (3)

राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है। अन्य 3 कथन सही हैं।

ऑपरेशन के दौरान, प्रदेश कार्यकारिणी को खारिज कर दिया जाता है और राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर कर दिया जाता है । राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य

प्रशासन और संसद राज्य के लिए कानून बना देते है। संक्षेप में, राज्य के कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र द्वारा ग्रहण की जाती है |

6. भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करने के प्रावधान क्या है?

1. न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है,जिसके लिए विधायिका को वोट करने की आवश्यकता नहीं है।
2. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
3. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है ।
4. भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही सरकार द्वारा की जाती है |

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. केवल 1
2. 1 और 4
3. 1, 2 और 3
4. 1, 2, 3 और 4

Solution (2)

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के एक आदेश से हटाया जा सकता है,जिसमे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं , किन्तु संसद के प्रत्येक सदन का एक विशेष बहुमत होना आवश्यक है |

वाक्य 3 - सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है - यह सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता की

निगरानी करता है , (यह प्रावधान कार्यकारी के पूर्ण निर्णय को संक्षिप्त करता है , साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियाँ किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं है।)

लेकिन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए , सबसे सही विकल्प २ होगा, अर्थात वाकया १ और ४ सही है |

7. भारतीय संदर्भ में, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बदल सकते हैं ?

1. संसद
2. भारत के राष्ट्रपति
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. चिंतित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

Solution (1)

संविधान संसद और राज्य विधायिका को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को बदलने के लिए शक्तियां प्रदान है।

8. निम्नलिखित मामलों में से कौन सा में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने में अनुचित है?

1. राज्य में कुशासन
2. त्रिशंकु विधानसभा के मामले में
3. मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप
4. केंद्र सरकार की एक संवैधानिक दिशा में राज्य सरकार द्वारा अवहेलना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 2, 3 और 4

2. केवल 1 और 3
3. केवल 4
4. 1, 2 और 4

Solution (2)

एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उचित होगा - जब वहाँ विधानसभा के आम चुनाव के बाद, कोई भी पार्टी बहुमत सुरक्षित नहीं करती है जो कि 'त्रिशंकु विधानसभा' है; और राज्य या मंत्रालय या राज्य के कड़े वित्तीय मजबूरियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में कुशासन अनुचित है ।

9. विचार कीजिये :

1. वित्तीय आपात स्थिति की कार्रवाई के दौरान, राज्य सरकार की सेवा करने वाली केंद्रीय अधिकारियों के वेतन कम किये जा सकते है
2. राष्ट्रीय आपात स्थिति की कार्रवाई के दौरान, केंद्र सरकार किसी भी मामले पर राज्य में कार्यकारी निर्देश देने के लिए हकदार हो जाता है।
3. वित्तीय आपात स्थिति की कार्रवाई के दौरान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कम किये जा सकते है

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 1 और 2
2. 1 और 3
3. 2 और 3
4. 1, 2 और 3

Solution (4)

राष्ट्रीय आपात स्थिति की कार्रवाई के दौरान (अनुच्छेद 352 के तहत), केंद्र सरकार किसी भी मामले पर राज्य में कार्यकारी निर्देश देने के लिए हकदार हो जाता है। इस प्रकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पुरे नियंत्रण में लायी जाती है हालांकि, वे निलंबित नहीं होते हैं।

एक वित्तीय आपात स्थिति के आपरेशन के दौरान (अनुच्छेद 360) के तहत केंद्र सरकार वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने में राज्यों प्रत्यक्ष कर सकते हैं और राष्ट्रपति राज्य में सेवारत व्यक्तियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कमी सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

10. विचार कीजिये :

1. एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिख कर उसकी / उसके कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है
2. संवैधानिक मामले न्यूनतम तीन न्यायाधीशों से मिलकर एक बेंच द्वारा सुलझाये जाते है
3. भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 1 और 3
2. केवल 2
3. 1, 2 और 3
4. 2 और 3

Solution (2)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते है न कि राज्यपाल द्वारा। कथन 2 सही है। संविधान पीठ भारत के संविधान के "व्याख्या करने के लिए के रूप में कानून का एक बड़ा सवाल को शामिल" किसी भी मामले में फैसला करने के लिए बैठते हैं,

जो अदालत के कम से कम पांच न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के बेंच को दिया नाम है।

11. **हाल के दिनों में भारत की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें**

1. 0-14 आयु वर्ग के आयु वर्ग में आबादी की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति है।
2. गरीब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण बुजुर्ग (60 +) के प्रतिशत में गिरावट का रुख है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. केवल 1
2. केवल 2
3. दोनों
4. कोई नहीं

Solution- 4

यह बिल्कुल विपरीत है। 0-14 वर्ष की आयु समूह में गिरावट आई है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, बुजुर्गों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

12. आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत का विकास करने में जो बाधाए हैं

1. बच्चों की आबादी बढ़ रही है
2. जनसंख्या पिरामिड के आधार पर मानव पूंजी की अपर्याप्तता
3. बुनियादी कौशल का अभाव

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 1, 2 और 3

2. 2 और 3
3. 1 और 3
4. 1 और 2

Solution- 2

बच्चों की आबादी में गिरावट, मानव पूंजी में अपर्याप्तता और बुनियादी कौशल की कमी

13. उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, समानता, गुणवत्ता और नवाचार में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार की पहल क्या हैं

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
2. सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
3. मिड डे मील (MDM)
4. टैक्निकल एज्युकेशन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP)
5. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF).

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 1, 2, 4 और 5
2. 1, 4 और 5
3. 2, 3 और 4
4. 2, 3 और 5

Solution- 2

सर्वेक्षण के अनुसार

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
2. टैक्निकल एज्युकेशन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP)
3. राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF).

14. मुख्यधारा के विकास में अल्पसंख्यकों को लाने की पहल का उद्देश्य है कि

1. नई मंज़िल
2. MANAS
3. नई रौशनी
4. USTTAD

नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करे :

1. 1, 2, 3 और 4
2. 2, 3 और 4
3. 1, 3 और 4
4. 1, 2 और 4

Solution- 1

सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हैं

15. विचार कीजिये

1. कपड़ा उद्योग
2. IT/BPO
3. धातु उद्योग
4. चमड़ा उद्योग

रोजगार सृजन के घटते क्रम में ऊपर क्षेत्रों की व्यवस्था कीजिये

1. 3-2-4-1
2. 1-2-3-4
3. 2-1-3-4
4. 2-1-4-3

Solution- 2

आर्थिक सर्वेक्षण

उद्योग के स्तर पर, परिधान क्षेत्र में रोजगार में उच्चतम छलांग देखी गयी, जहां रोजगार मार्च 2014 से अधिक जून 2014 के दौरान 69,000 की वृद्धि हुई है, आईटी / बीपीओ में 51,000, धातुओं में 47,000, 7000 प्रत्येक चमड़ा और रत्न और आभूषण में , और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 1000।